RAJYA SABHA

Wednesday, the 8th December, 1999/17 Agrahayana, 1921 (Saka)

The House met at Eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*141. [*The questioner (Shri Bhagaban Majhi) was absent* for answer, *vide page 22 intra*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 142, Mr. Rama Shanker Kaushik.

भारतीय परिधानों के निर्यात पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा पाबंदी लगाया जाना

*142. श्री रमा शंकर कौशिक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत से यूरोपीय देशों को निर्यात किये जाने वाले परिधानों पर पाबंदी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त संगठन द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार की पाबंदियों को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Ban on export of Indian Garments by EEC

†*142. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether European Economic Community have imposed ban on garments to be exported to European countries from India;

(b) if so, what reasons have been given by the organisation in this regard; and

(c) what action Government are going to take to do away with such restrictions?

† Original notice of the question was received in Hindi.

420 RS

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Question do not arise.

श्री रमा शंकर कौशिकः श्रीमन्, हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें इन्होंने लिखा है कि (क) "जी नहीं", (ख) और (ग) "प्रश्न नहीं उठता है"। यहां ये कह रहे हैं कि टेबल पर एक स्टेटमेंट रखा गया है। तो टेबल पर इन्होंने क्या रखा है यह पता नहीं है। क्या स्टेटमेंट रखा है टेबल पर?

श्री काशीराम राणाः सभापति महोदय, इन्होंने पूछा है कि "Whether European Economic Community have imposed ban on garments to be exported to European countries from India."

सर, ऐसा कोई बैन लगा ही नहीं है, इसलिए मैंने "न" में जवाब दिया है।

श्री रमा शंकर कौशिकः यही तो जवाब आना चाहिए था। इन्हें (क) भाग का यह जवाब देना चाहिए था कि "जी नहीं" और (ख) और (ग) का यह जवाब देना चाहिए था कि "प्रश्न नहीं उठता है"। अगर कोई स्टेटमेंट होता तो उसे ये टेबल पर रखते।

श्री काशीराम राणाः रिप्लाई में "जी नहीं", है।

श्री संघ प्रिय गौतमः इन्होंने सदन का समय बचाया है।

श्री रमा शंकर कौशिकः श्रीमन्, हमारा जो कुल निर्यात होता है उसमें 30 प्रतिशत हिस्सा वस्त्र निर्यात का है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 1996-97 में 41,828 करोड़ 15 लाख रुपए का वस्त्र निर्यात हुआ था और 1997-98 में 46,278 करोड़ 61 लाख रुपए का वस्त्र निर्यात हुआ। इस तरह इसमें 10.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1998-99 में वस्त्र निर्यात में बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या रहा है।

श्री काशीराम राणाः माननीय सभापति जी, माननीय सांसद श्री ने सही कहा है कि 1996-97 में हमारा एक्सपोर्ट 41828.2 करोड़ का हुआ था। वैसे ही 1997-98 में 46092.5 करोड़ और 1998-99 में 52720.8 करोड़ का यानी 14.4 की बढ़ोतरी हुई है। जबकि इसके पहले सिर्फ 10.2 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन बाद में 14.4 की बढ़ोतरी हुई है और अभी मैं लेटेस्ट फिगर्स आपको देना चाहूंगा, आगस्ट हाउस को कि अप्रैल से सितम्बर, 99 में 26994.7 यानी 6.1 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। हमें विश्वास है कि हम इससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिकः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जिसका मैंने शुरू में निवेदन किया कि हमारे कुल निर्यात का, भारत से जो भी चीजें निर्यात

4280 RS-IB

होती है उसमें 30 प्रतिशत वस्त्र उद्योग से हमें प्राप्त होता है, तो इसका प्रतिशत क्या है? प्रश्न नम्बर एक। -

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 1974 से आईएमएस के अन्तर्गत द्विपक्षीय करार जो होते थे, उन करारों के तहत वह किया जाता था। लेकिन 1995 से उरूग्वे की बैठक के बाद जो प्रतिबन्ध लगा है, उस प्रतिबन्ध का असर हमारे वस्त्र निर्यात पर कितना पड़ा है, क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताने की कृपा करेंगे?

श्री काशीराम राणा: माननीय सभापति जी, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है उसमें टेक्सटाइल का प्रतिशत कितना है यह माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। मैंने जैसे कहा कि 1998-99 में जो हमारा 52720.8 करोड़ रुपये का हुआ था, ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट जो पूरे देश का हुआ था वह 141603.5 का हुआ था। यह जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट हुआ था उसमें से हमारा 52520.8 का एक्सपोर्ट हुआ था, यानी ओवरआल एक्सपोर्ट में हमारा 37.25 परसेंट था। यह हमारी टेक्सटाइल से, ओवरआल यह हमारी टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है।

दूसरा प्रश्न का पार्ट है कि प्रतिबन्ध का कितना इफेक्ट रहा है। माननीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध गारमेंट के ऊपर नहीं लगा है यानी इसका कोई उल्टा असर हमारे ऊपर नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी-कभी किसी प्रकार की कमी आ जाती है, उसमें एंटी-डम्पिंग का प्राब्लम आ जाता है। लेकिन उसको हम एमिकेबली रिजाल्व कर लेते हैं, इसलिए यह कोई प्राब्लम नहीं है। मैं एक एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा कि जैसे हमें एक्सेप्सनल फ्लेक्सेबिलिटी मिलती है, जितने भी हमारे पास एग्रीमेंट हैं वह हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें एक्सेप्सनल फ्लेक्सेबिलिटी मिलती है और हमने 95 में, 96 में 7000 टन हमने एक्सेप्सनल फ्लेक्सेबिलिटी के रूप में एक्सपोर्ट किया था। जब 1997 में जो 7000 फ्लेक्सेबिलिटी थी उसमें हमने 50 परसेंट किया था। यह जो एम्बार्गो लगा था जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, उस रिक्वेस्ट को कभी-कभी कबूल करते हैं वह हमारा राइट नहीं होता है, लेकिन महारी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जो एम्बार्गो लगा था हमारे टेक्साइल में वह 99 में एडजस्ट कर दिया गया।

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मंत्री जी का जो महकमा है, वस्त्र का इसमे काफी एक्सपोर्ट होता है। गुजरात में शुरू से एक्सपोर्ट होता है और वहां पर बड़ा भारी कपड़े का व्यापार है। आपने जो आंकड़े यहां पर रखे हैं, उनके हिसाब से तो एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना होते हुए भी—एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, आपने फिगर्स बताई 14.4 प्रतिशत ज्यादा हो रहा है तो यह एक प्रोसेस है। तो सूरत में, देश में यह फेल क्यों हो रहा है क्या आप मुझे बतायेंगे? गवर्नमेंट की ऐसी पालिसी नहीं है जिसकी वजह से दो-तीन साल में फाल डाउन आया है,

जगह-जगह प्रोसेस हाउस बन्द हुए हैं और जगह-जगह यूनिट्स सिक पड़े हैं, तो आप इनके लिए क्या करेंगे और क्या आप बतायेंगे कि इसके क्या कारण हैं?

MR. CHAIRMAN: This question does not arise out of this. Now, Shri Narendra Mohan.

श्री नरेन्द्र मोहन: सर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे यह बात तो साफ हो रही है कि वस्त्र उद्योग में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है, केवल कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है। यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वस्त्र उद्योग के निर्यात में उतनी बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो पा रही है जितनी योजना आयोग ने आशा की थी और आश्वासन दिये थे। वस्त्र उद्योग की स्थिति भारत में निश्चित रूप से आज बहुत दयनीय है। इस दयनीय स्थिति के रहते हुए वस्त्र उद्योग का उतना निर्यात नहीं हो सका जितनी कि आशा की जाती थी। हमारे यहां पावरलूम हैं, हैंडलूम हैं, सूती मिलें हैं और ऊनी मिलें हैं। कृपया मंत्री जी हमें बताएं कि वस्त्र उद्योग की वास्तविक स्थिति क्या है और आधुनिकतम स्थिति कब बनेगी ताकि निर्यात के क्षेत्र में यह चीन सरीके राष्ट्रों का मुकाबला कर सके? हम निर्यात के क्षेत्र में वे उपलब्धियां क्यों नहीं पा रहे हैं जो कि हम पा सकते थे?

श्री काशीराम राणा: महोदय, यह ठीक है कि जिस अपेक्षा से हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए, वह इस साल और गत साल नहीं बढ़ा। इसके लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। चीन का एक्सपोर्ट में टोटल वर्ल्ड शेयर 26 परसेंट है जबकि हमारा तीन परसेंट है। इसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं।। चाइना का एग्जाम्पल दिया गया। वहां टेक्सटाइल रिफोर्मर्स किए गए और इम्पलीमेंट किए गए। हम भी इसी प्रकार से बुहत सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हमारे फेब्रिक्स अच्छे हों और इसके साथ-साथ आफोरडेबल प्राइस पर हमारा फेब्रिक बने। इसीलिए हमने टैक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम शुरू की है। हम कॉटन टेक्नोलोजी मिशन शुरू करने जा रहे हैं और न्यू टेक्सटाइल पालिसी बनाने जा रहे हैं। जब तक हम टैक्सटाइल का रिफोर्म्स इम्पलीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए दुनिया में कंपीटीटर्स के साथ कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसको आसान करने के लिए ही हम ये स्टेप्स ले रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: महोदय, यही तो मेरा प्रश्न है कि जो रिफोर्म्स की बात मंत्री जी कर रहे हैं वह कब तक पूरे होंगे, कब तक हम भारत के वस्त्र उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सकेंगे?

श्री काशीराम राणा: जो स्टेप्स हमारी मिनिस्ट्री ले रही है इससे हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आएंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: महोदय, यह तो एक प्रकार से मेरे प्रश्न की उपेक्षा हुई।

श्री काशीराम राणा: 25,000 करोड़ का टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन फंड जो कि हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारी सरकार ने इम्पलीमेंट करने की कोशिश की है। नई टैक्सटाइल पॉलिसी भी शायद बजट सेशन से पहले ही देश के सामने आ जाएगी। हमारे कॉटन की क्वालिटी दुनिया के कॉटन की क्वालिटी से इन्फीरियर होती है। हमने कॉटन टैक्नोलोजी मिशन स्थापित किया है इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और माल भी सस्ता बनेगा। इसलिए हम ऐसे रिफोर्म्स शुरू करने जा रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: चेयरमैन साहब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

MR. CHAIRMAN: That is over. You cannot ask any more questions. Your turn is over. ....(*Interruptions*)... Now, that is all right. Yes, Mr. Bommai.

SHRI S.R. BOMMAI: Mr Chairman, Sir, the garment industry is the greatest employer in this country. The export has been increasing, but now, slowly, it is coming down because other countries are coming in competition. Now, I would like to know, what plans the Government has to meet the competition from other countries?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I have already told the august House that my Ministry is going to take some steps. Our exporters are also taking some steps to convince the foreign importers and the importing countries. Not only that; other plans are also being taken up by my Ministry to improve the exports.

श्री रूमन्दला रामचन्द्रैया: सभापति महोदय, भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक से कितना हो रहा है, कृपया मंत्री जी बताएं।

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the question does not arise.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

PROF. (SMT.) BHARATI RAY: Mr. Chairman, Sir, there is a report that the European Union (E.U.) is planning to ban the use of about 300 textile dyes. In 1996, Germany had banned the entry of textiles and some items using chemicals and dyes which were not found to be eco-friendly. Following Germany, the Netherlands also banned the import of certain goods, like clothing, bed covers, chair covers, because it was alleged that some dyes, which may cause

cancer were being used in them. No, the EU based cloth producers or manufacturers have phased out the use of the so called "dangerous dyes". Is the Government of India aware of this! Is it taking steps to advise and assist the textile industry in this regard so that we do not face a ban? This is part (a).

Part (b) is relating to the answer given by the hon. Minister about fashion and marketing of superior quality of cotton and cotton goods. The fashion industry is changing very fast in the world. Now we have to face the challenge of industrial competition on the global plane. What is the Government thinking or planning to do to collaborate, interact, with the fashion industry of the world so that our textiles, which are of a very good quality, can meet the challenge?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, so far as dyes are concerned, the German Government has done some type of imposition. The Textile Research Association under my Ministry, after scrutinising it, has already banned 116 dyes. After that, the Netherlands is taking some objection, so far as these dyes are concerned; not about garments, but particularly about carpets. This is not a problem now because we have alrady banned 116 dyes. Those dyes are definitely harmful to people.

Sir, the second part of the question is about the fashion technology. Sir, we are expanding our base, our network. The NIFT is going to offer some more courses in the country. Moreover, we are also taking some steps. We have started evening courses also in the country. So, we are taking some steps.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Thank you, Mr. Chairman, Sir. Some EU officials have said that the Euro-line MNCs insist that their suppliers should deal only in Euro. I want to have this clarification from the Minister: Is it true that only Euro will be accepted by the importers there and that India has repeatedly violated the pact on textile products? This is the claim of the EC. I want to have this clarification whether it is true or it is not true. Or, is it only to avoid getting exports from India?

Finally, jute is also part of textiles. A lot of jute garments can be made. Is the Government trying to do something so that cotton mixed with jute or jute mixed with cotton, whatever it is, can also be exported? What efforts is the Government making on this?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, it is not totally true that our exporters are violating some type of conditions.

The second part is about jute garments. It is correct that, so far as jute is concerned, our exports are declining. But now the Government of India is going to formulate a Technology Mission on Jute so that we can improve the quality of jute. We can enhance our productivity of jute also. So, in this way, we can improve the jute technology.

Offence of untouchability against SCs

*143. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of offence of untouchability, committee against scheduled castes, registered during 1998 and 1999, State-wise;

(b) whether there is a provision under the Civil Rights Protection Act, 1995 to identify untouchability prone areas in the country and submit a periodical report to Parliament in every three years; and

(c) if so, how many such reports have been submitted during the last ten years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) **Available information is given in the enclosed Statment-I** (*See* below).

(b) and (c) Section 15A(2) of the Protection of Civil Rights Act, 1955 provides, inter alia, for the identification of the areas where persons are under any disability arising out of "untouchability" and adoption of such measures as would ensure the removal of such disability from such areas. Further, section 15A (4) of the Act provides for placing on the Table of each House of Parliament, every year, a report on the measures taken by the Government of India